उनके अंतरिक्ष में ही उड़ान की सफलता है । इस उड़ान की सुरक्षा पर हजारों की जानें निर्भर हैं, कृपया हमें कोई सकारात्मक उत्तर दें । धन्यवाद ।

MR. CHAIRMAN: Why do we go so back? We can go back to Ramayana. Rawana also defeated Jatayu.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, it was basically their territory which we have encroached in the modern age. But this is a worldwide phenomenon. It is not there only in our country. Of course, keeping in view the general culture as it is in our country, we have more bird hits as compared to the rest of the world. Then you cannot say that this is the only area because in our surroundings we have hutments and we don't have cleanliness to the extent which other countries have.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Sir, the problem of bird-hits in some other countries is solved by using certain species of birds called African Falcon. In our country this bird is not permitted to be imported by the Ministry of Environment and Forests because the Minister wants to protect wildlife. He has compassion for the wildlife I have no objection to that. But the Minister of Civil Aviation should also have some concern for human lives. May I know from the hon. Minister whether this particular bird will be permitted to be imported in our country for a specific purpose as a special case? He has compassion for wildlife.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, some countries are making use of this particular bird. But we are being told that it is no more successful As far as our country is concerned. Some time back, at attempt was made to do it. But at that time the Ministry of Environment did not allow it. That is why, it is not being done.

MR. CHAIRMAN: Question No. 544.

Inflow of FDI in the country

*544. SHRI G. G. SWELL:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:†

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of Foreign Direct Investment proposals approved since 1991, yearwise figures of amount involved in FDI proposals and invested so far;

(b) what is the actual inflow of FDI, till date;

(c) what are the more beneficial tax concessions to FDI as compared to Indian and NRI investment;

(d) what are the industries where 100 percent and 50 percent FDI is allowed, separately; and

(e) whether there is a proposal for 75 percent FDI equity to be approved automatically?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Number and amount of foreign direct investment proposals approved since 1991 to 1994 (up to March) are as under:—

(Rupees in crores)

Year	No. of Foreign direct Investment proposals approved	Amount of Foreign direct Investment approved
1991	289	534 11
1992	692	3887 54
1993	785	8859.33
1994 (up to March, 1994)	211	1175.10

† [ ] The question was actually asked on the floor of the House by Shri Chimanbhai Mehta.

(b) The actual inflow of foreign direct investment from 1991 to March 1994 is estimated at Rs. 3406.6 crores.

(c) The Income Tax Act provides certain concessional tax rates uniformly to non-residents including NRIs.

(d) The new industrial policy does not lay any restriction in regard to the percentage of foreign equity holdings in Indian joint ventures. While the facility for automatic approval by RBI for foreign equity upto 51 per cent is available subject to prescribed norms, proposals for higher equity participation, even upto hundreds percent, are received and considered by the Government on merits.

(e) No, Sir.

श्री चिमनभाई मेहता : सर, जो आंसर दिया गया है उसमें बताया गया है कि करीबन 5 बिलियन डालर इस देश में तीन वर्ष में डायरेक्ट इंवेस्टमेंट के रूप में आये हैं । लेकिन जो इंवेस्टमेंट का एप्रूवल आपने दिया, क्लियरेंस किया, उसके बाद यहां जो पूंजी लगनी चाहिये उसमें काफी विलंब होता रहा है । जब आपने 14595 करोड़ का क्लियरेंस दे दिया तब आज तक सिर्फ 3400 करोड़ का इवेस्टमेंट ठीक है । साइजेबिल इसलिये आपको लगता है, लेकिन जब क्लियरेंस दिया गया है वह 15 हजार करोड़ का है और उसके मुकाबले में साढ़े तीन हजार करोड़ का इनफलों आ चुका है । मैं नहीं कहता हूं कि यह स्माल एमांउट है । लेकिन देर लगती है और जो इंवेस्टमेंट जल्दी से आना चाहिये उसमें कहां रूकावट होती है । मंत्री महोदय, स्टेट गवर्नमेंट को आपको जो कोआपरेशन देना चाहिये लैंड के बारे में, वाटर के बारे में, इलैक्ट्रिसिटी के बारे में वह नहीं मिल रहा है । तो उसके लिये कोआर्डिनेशन करने के लिये जल्दी इनफलो हो, उसके बारे में आप कोई प्रबंध सोच रहे हैं या नहीं ? उसका रेस्पोंस क्या मिला है, वह आप बताइये ?

श्रीमती कृष्णा साही : सभापति महोदय, 1991 से मार्च, 94 तक लगभग 3407 करोड़ की विदेशी पूंजी प्राप्त हो चुकी है, जैसा माननीय सदस्य भी मानते हैं । तो बहुत से प्रोजेक्ट में हाल में स्वीकृति प्रदान की गई है और प्रोजेक्ट के प्रारंभ होने में समय तो लगेगा ही । लगभग 50 प्रतिशत स्वीकृति बड़े प्रोजेक्ट के लिये है जिसमें काफी समय लगता है । आज आप किसी की स्वीकृति देते हैं, 50 प्रतिशत बड़े प्रोजेक्ट की है, तो आज ही तो वह नहीं खड़ा हो जायेगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा और 80 प्रतिशत से अधिक इवेस्टमेंट हमारे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में एप्रूव किये गये है । तो जब ऐसे क्षेत्रों में हम स्वीकृति करते हैं तो उसमें समय लगता है । दूसरी बात उन्होंने कही है कि ज्यादा इनफलो स्टेटस में भी हो, इसके लिये सरकार क्या कर रही है?

श्री चिमनभाई मेहता : स्टेटस को कोआपरेशन जितना देना चाहिये, नहीं मिल रहा है । उसी वजह से देर हो रही है ।

श्रीमती कृष्णा साही : सभापति महोदय, भारत सरकार ने इसके लिये समय-समय पर स्टेटस के उद्योग मंत्रियों, मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया है, उन्हें निर्देश दिया गया है । हमारे यहां के जो पदाधिकारी

हैं और मैं भी स्वयं स्टेटस में गई हूं और वहां के उद्योग मंत्रियों के साथ हमने वार्ता की है और उन्हें हमने रास्ता बताया है कि आप किस तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, ताकि फारेन इवैस्टर्स आपकी तरफ आकर्षित हों। अभी हाल में, पहले तो हमने तीन-चार बड़े-बड़े सम्मेलन बुलाए हैं। अभी हाल में सारे प्रांतों के मुख्य सचिवों का यहां एक सम्मेलन बुलाया है और उस सम्मेलन में उन लोगों को डायरेक्शन दिया गया है और गुजरात के मुख्य सचिव संभवत इसके अध्यक्ष हैं और सारे प्रांतों को कोआर्डिनेट करके जिस तरह से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो और कैसे विदेशी पूंजी वहां आकर्षित की जा सके, इसके लिये विचार विमर्श हुआ है और उनको रास्ते बताये गये हैं। कार्यान्वयन की दिशा में किस तरह शीघ्र कार्रवाई की जाय, इस पर कार्रवाई की गई है।

श्री सभापति : सेकेंड सप्लीमेंट्री, प्लीज।

श्री चिमनभाई मेहता : वैसे तो मैंने कहा कि आपने करीब 15 हजार करोड़ विदेशी पूंजी को आकर्षित किया है। लेकिन भारत का जो पुटेंशियल जो पूरी दुनियां में माना जा रहा है कि यहां काफी पूंजी लगाई जा सकती है, ज्यादा लगाई जा सकती है। मैं इसलिये कम्पेरेजन कर रहा हूं कि चीन हमारा पड़ौसी देश है और वहां जो विदेशी पूंजी है उसका एट्रेक्शन ज्यादा जोर से हो रहा है। करीबन 55 बिलियन डालर तक वह पहुंच गये हैं। इतना फारेन इंवेस्टमेंट वहां हो चुका है। हमारे यहां जो कम हो रहा है उनके मुकाबले में, तो उसकी वजह क्या है ? वह किस तरह से आकर्षित करते है और हम किस तरह से आकर्षित नहीं कर पाते हैं ? वह दोनों हमें देखना चाहिये। अगर आप बता सकते हैं तो बताइये।

श्रीमती कृष्णा साहो : सभापति महोदय, एशियाई देशों में चीन, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, इंडोनेशिया एवं कुछ अन्य देशों की तुलना भारत से की जाती है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि इन देशों ने अपनी आर्थिक नीतियों का उदारीकरण और सुधार बहुत पहले ही प्रारंभ कर दिया था ताकि उनके देश में विदेशी पूंजी आकर्षित हो सके। चीन ने 1979 में कर दिया था, इंडोनेशिया ने भी पहले ही कर लिया था। हमने बहुत पीछे प्रारंभ किया है। फिर भी हमें लोग उन देशों की तुलना में आगे जा रहे हैं और एशियाई देशों में चीन के बारे में उन्होंने चर्चा की है।

तो चीन ने जो काम किया है, हम उससे पीछे नहीं हैं, हम भी उसी दिशा में जा रहे है लेकिन भारत से सब देशों की तुलना तो नहीं की जा सकती। हमारा तो प्रजातंत्र है, हम सबों को साथ लेकर चलते हैं, संसद को साथ लेकर चलते हैं, सभी की बात मानते हैं। इस तरह से हम आगे बढ रहे हैं लेकिन मैंने आपको बताया है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपको मैंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री गया सिंह : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से जो अभी बता रही हैं कि काफी विदेशी पूंजी निवेश हुआ है, जानना चाहता हूं कि किस-किस तरह की इंडस्ट्रीज में हुआ है और अगर वे कुछ खास राज्यों की ओर इंडिकेशन कर दें कि यहां हो रहा है तो क्लियर हो जाएगा।

इसी से संबंधित दूसरी बात यह है कि अभी पावर सैक्टर में 4–5 मल्टी नेशनल्स हमारे देश में पैसा लगा रहे हैं लेकिन जो लागत है, प्रति मैगावाट का हिंदुस्तान का ऐस्टीमेट है, उससे डबल पैसा देकर आप विदेशी पूंजी का निवेश कर रहे हैं। इसके बारे में मंत्री जी को अगर जानकारी है तो बताए।

श्रीमती कृष्णा साही : वह प्रश्न तो पावर मंत्रालय से संबंधित है। जो उन्होंने पूछा है कि किस-किस सैक्टर में हो रहा है तो मैं यह बताना चाहती हू कि कप्यूटर-सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रोनिक्स, आयल-रिफाइनरी, टेलीकम्युनिकेशन, स्प्रे-ड्राईड सिलिका, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, टेक्नोलोजी इन्फॉरमेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट सर्विसेज, इजीनियरिंग, ऐडहैसिव्ज, साईट्रिक एसिड, फूड प्रोसेसिंग एलाईड इडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, डॉयग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल इस्टीट्यूशस, होटल आदि। यह इनका सैक्टरवाईज, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया है।

DR. BIPLAB DASGUPTA: Having looked at the figures, I find that the rate of inflow of direct foreign investment has been showing down. If you compare the figures of 1993 with those of 1994 up to March, it indicates that even on its own terms the new economic policy is failing because so much was put in store on the help to be given by foreign capital to rescue India from the present desperate situation. That has has obviously failed. I would also like to ask the Prime Minister if he can name a single country in the world, including South Korea, Taiwan and Hong Kong, which has developed while ignoring its domestic industries, not giving protection to the domectic industry. Has any such country succeeded in ensuring development simply by inviting foreign capital?

THE PRIME MINISTER (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): Sir, I would only include India in the list of all those countries. We have also not neglected the domestic industry. The domestic industry is extremely happy with the new policy and they have demonstrated it so many times.

SHRI S. JAIPAL REDDY: The domestic industry is unhappy. (*Interruptions*) The Prime Minister should not make this kind of a statement. He has made an incorrect statement. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: There cannot be a volley of questions, please. I will call somebody for question. Everybody cannot ask simultaneously. Mr. Bommai to put his question.

SHRI SOMAPPA R. BOMMAI: The statement at (a) shows that approval has been given for investment of Rs. 14,341 crores. But the actual investment is Rs. 3,406 crores. And the difference shows the failure of our policy to attract foreign investment. I would like to know what the reasons are. Is it a failure of policy or is it due to red-tapism and other things?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.